दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 19 अक्टूबर 2023

रि.या.(आप.) 2416/2023

आशीष मित्तल ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री शिखर शर्मा, श्री मयंक शर्मा और श्री हर्ष गौतम, अधिवक्तागण।

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुपम एस. शर्मा, विशेष अधिवक्ता सह श्री प्रकाश एरन, सुश्री गुरप्रीत कलसी, श्री रिपुदमन शर्मा, श्री अभिषेक बत्रा और श्री वशिष्ठ राव, प्रत्यर्थीगण/ईडी के लिए अधिवक्तागण।

माननीय न्यायाधीश श्री अनूप जयराम भंभानी

<u>निर्णय</u>

न्या. अनूप जयराम भंभानी

रि.या.(आप.) 2416/2023 एवं आप.वि.अ. 22727/2023

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ("दं.प्र.सं.") की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता/आशीष मित्तल, प्रत्यर्थीगण/प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") द्वारा 04.03.2020 को दर्ज ईसीआईआर सं. ईसीआईआर/डीएलजेडओ-I/04/2020 को अभिखंडित करने के निर्देश की मांग करता है। दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत दायर आप.वि.आ. सं. 22727/2023 के साथ संलग्न आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता ने ईडी द्वारा "ईसीआईआर सं. ईसीआईआर/डीएलजेडओ-आई/04/2020 से निकलने वाली पूरी कार्यवाही और अब जांच की जा रही कार्यवाही पर रोक लगाने" की; और एक और निर्देश देने की मांग की है कि ईडी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने के लिए कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाए।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

2. याचिकाकर्ता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए उकसाने वाले मुख्य कारण हैं - दिनांक 18.08.2023 के समन, जो उसे सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

("पीएमएलए") की धारा 50(2) और (3) के अंतर्गत जारी किए गए थे, जिसमें याचिकाकर्ता को 21.08.2023 को ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।

3. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि उसे *"...इस बात की प्रबल आशंका है कि उसे प्रत्यर्थीगण द्वारा अवैध रूप से निरुद्ध/गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कंपनी के मुख्य संप्रवर्तकों/कथित मुख्य लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उसे बलि का बकरा बनाया जाएगा ..."*

4. विशेष रूप से, याचिका के साथ आक्षेपित ईसीआईआर की एक प्रति दायर नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे आज तक आक्षेपित ईसीआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

<u>प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स</u>

5. संक्षेप में, वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक मामले की रूपरेखा निम्नलिखित है :

   5.1. कहा गया है कि आक्षेपित ईसीआईआर प्रत्यर्थीगण द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ('सीबीआई') द्वारा सीबीआई, बीएसएफबी, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता, 1860 ("भा.दं.सं.") की धारा 420/467/468/471 के साथ पठित धारा 120ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत दर्ज

प्राथमिकी सं. आरसीबीडी1/2020/ई/0002 दिनांक 10.02.2020 के आधार पर पंजीकृत की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, धोखाधड़ी के प्रयोजनों के लिए जालसाजी, जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करना और मैसर्स एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड ("ईएसएल") के मामलों के संबंध में 2012 के बाद से किए गए आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 06.02.2020 को की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया है; हालांकि, याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं है;

5.2. आक्षेपित ईसीआईआर में पीएमएलए की धारा 3 और 4 के अंतर्गत 'धन शोधन' के अपराध का आरोप लगाया है;

5.3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, आक्षेपित ईसीआईआर अभिलेख में नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास इसकी प्रति नहीं है;

5.4. याचिकाकर्ता ईएसएल के साथ लगभग साढ़े तीन वर्षों तक जुड़ा रहा, शुरुआत में 01.11.2013 से वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) के रूप में; और

उसके बाद 26.05.2014 से इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी.एफ.ओ.) के रूप में। उसका तर्क है कि वह ईएसएल के लिए एक निगमित ऋण पुनर्गठन योजना को लागू करने के लिए सी.एफ.ओ. के रूप में कार्यरत था;

5.5. याचिकाकर्ता तर्क देता है कि वह कभी भी कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं था, न ही वह लेखा परीक्षा समिति सहित किसी भी विधिक समिति का हिस्सा था, न ही कंपनी का शेयरधारक था; और उसने दिनांक 24.02.2018 के त्याग पत्र के माध्यम से कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया था;

5.6. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि कंपनी के साथ उसके कार्यकाल के दौरान सभी लेनदेन ऋणदाता बैंकों की निगरानी समिति और/या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत ईएसएल के विरुद्ध कार्यवाही में नियुक्त समाधान पेशेवर की सहमति और जानकारी के साथ हुए थे।

5.7. दूसरी ओर, यह टिप्पणी की गई है कि याचिकाकर्ता भा.दं.सं. की धारा 420/120ख, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211/628/227/233 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129/447/448 के अंतर्गत

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ("एसएफआईओ") द्वारा दायर सीटी केस सं. 990/2022 वाले आपराधिक शिकायत मामले के भी अभियुक्तगण में से एक है, जिस मामले में उसे लगभग 07 महीने की अभिरक्षा में रहने के बाद ***आशीष मित्तल बनाम गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय*** शीर्षक वाले जमानत आवेदन सं. 251/2023 में दिनांक 03.05.2023 के निर्णय के अंतर्गत जमानत दी गई थी।

6. हालांकि वर्तमान याचिका पर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थीगण ने पूर्व-निर्धारित उत्तर के माध्यम से दिनांक 31.08.2023 का उत्तर-शपथपत्र दाखिल करने का विकल्प चुना।

7. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर और प्रत्यर्थीगण/ईडी की ओर से उपस्थित विशेष अधिवक्ता श्री अनुपम एस. शर्मा को भी सुना। पक्षकारगण की ओर से लिखित प्रस्तुतियां भी दायर की गई हैं।

8. प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से, श्री शर्मा ने वर्तमान याचिका की धारणीयता का विरोध यह प्रस्तुत करते हुए किया है कि वर्तमान याचिका को दाखिल करने का कारण केवल पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जारी 18.08.2023 के समन हैं और इससे अधिक कुछ नहीं; और यह स्थापित विधि है कि समन पर रोक लगाने या अभिखंडित करने की मांग करने वाली

रिट याचिका धारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, श्री शर्मा प्रस्तुत करते हैं, कि किसी भी स्थिति में, वर्तमान याचिका *अपरिपक्व* है क्योंकि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का नाम पीएमएलए की योजना के अंतर्गत संज्ञेय/प्रतिपादित अपराध के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज *प्राथमिकी में नामित नहीं* है। हालांकि न तो ईसीआईआर और न ही उसके अनुसार दायर की गई अभियोजन शिकायत अभिलेख पर है, श्री शर्मा ने यह भी पुष्टि की है कि याचिकाकर्ता को *ईसीआईआर या इस प्रकार दायर अभियोजन शिकायत में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है।*

9. उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करते हुए, धारणीयता के मुद्दे पर पहले पक्षकारगण को सुनना आवश्यक समझा गया।

10. याचिका के *धारणीय नहीं होने* और/या *अपरिपक्व* होने के मुद्दे पर, दोनों पक्षकारगण के अधिवक्तागण ने अपने-अपने प्रस्तावों के समर्थन में व्याख्या करते हुए कई न्यायिक पूर्व निर्णयों का हवाला दिया है। हालांकि, एक ही बिंदु पर निर्णयों की बहुलता से बचने के लिए, केवल सबसे प्रासंगिक और भौतिक निर्णयों को ही यहां उद्धृत किया जा रहा है।

<u>विधिक परिदृश्य पर चर्चा</u>

<u>पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जारी समन के विरुद्ध अंतरिम राहत</u>

11. "कारण बताओ सूचना" के विरुद्ध रिट याचिका पर विचार करने के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, पहले के निर्णयों की एक शृंखला पर भरोसा करते हुए, ***भारत संघ बनाम कुनिसेट्टी सत्यनारायण*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के वैवेकिक रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग आमतौर पर कारण बताओ सूचना को अभिखंडित करके नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया गया हो जिसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, चूंकि मात्र एक कारण बताओ सूचना किसी वाद हेतुक को उत्पन्न नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि केवल कारण बताओ सूचना जारी करना किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल आदेश के बराबर नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि रिट याचिका तब दायर की जाती है जब किसी पक्ष के किसी अधिकार का अतिलंघन किया जाता है, इसलिए कारण बताओ सूचना (या आरोप पत्र) के विरुद्ध रिट याचिका पर विचार करना भी अपरिपक्व होगा। स्पष्ट रूप से, *कुनिसेट्टी सत्यनारायण* (पूर्वोक्त) एक ऐसा मामला था जो किसी सेवा विवाद से उत्पन्न हुआ था न कि किसी आपराधिक कार्यवाही से।

12. ***विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम घौस***, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत एक मामला था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> *"3. अपीलार्थीगण के अनुसार, रिट याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह कारण बताओ सूचना को चुनौती देती है और किसी भी स्थिति में कारण बताओ सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अंतिम राहत इस संबंध में किसी भी आगे की कार्रवाई को रोककर पारित अंतरिम आदेश द्वारा नहीं दी जानी चाहिए थी। यह बताया गया कि प्रत्यर्थी 1 लगभग 270 करोड़ रुपये से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है और दस्तावेजों में हेरफेर किया गया है, खातों में हेरफेर किया गया है; और किसी भी स्थिति में प्रत्यर्थी 1 उन सभी बिंदुओं को उजागर करने के लिए स्वतंत्र था जो नोटिस जारी करने वाले प्राधिकरण के समक्ष रिट याचिका में उठाए गए थे। ऐसा करने के बजाय, वह उच्च न्यायालय में चला गया और दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने न केवल रिट आवेदन पर विचार किया, बल्कि अंतरिम राहत भी प्रदान की, जो प्रभावी रूप से रिट याचिका को गुणागुण के आधार पर सुनवाई से पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अपने लिए मांगी गई अंतिम राहत, संक्षेप में, अंतरिम आदेश द्वारा प्रदान की गई थी। ..... उच्च न्यायालय को रिट याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए था।*
>
> * * * * *

"5 *[एड.: पैरा 5 को शुद्धिपत्र संख्या एफ.3/एड.बी.जे./40/2004 दिनांक 2-4-2004 द्वारा सही किया गया]। इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में उच्च न्यायालयों की कारण बताओ सूचनाओं, जो प्रस्तावित जांच को रोकते हैं और भागीदारी और पक्षकारगण की उपस्थिति में वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच प्रक्रिया को बाधित करते हैं, की वैधता पर प्रश्न उठाने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करने की प्रथा की निंदा की है।* ***जब तक उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि कारण बताओ सूचना विधि की नजर में पूरी तरह से गैर-मान्य थी, यहां तक कि तथ्यों की जांच करने के लिए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी के कारण, केवल प्रश्न करने के लिए और नियमित रूप से रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, और रिट याचिकाकर्ता को हमेशा कारण बताओ सूचना का जवाब देने और रिट याचिका में उजागर किए गए सभी मत लेने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।*** *क्या कारण बताओ सूचना किसी विधिक आधार पर स्थापित किया गया था, यह एक न्यायिक मुद्दा है जिस पर सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा भी आग्रह किया जा सकता है और ऐसे मुद्दों का न्यायनिर्णय शुरुआत में सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, इससे पहले कि पीड़ित न्यायालय का दरवाजा खटाखटा सके। इसके अतिरिक्त, जब न्यायालय अंतरिम आदेश पारित करता है तो उसे यह देखने में सावधानी बरतनी चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित विधिक पदाधिकारी मामले को शुरू में तय करने और अंतिम राहत सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों और अधिकार से वंचित न हों, जो रिट याचिका में अंतिम रूप से*

दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है, वह रिट याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम सुरक्षा की सीमा पर भी नहीं दी जाती है।"

(जोर दिया गया)

13. उपरोक्त स्थिति को ***किरीट श्रीमंकर बनाम भारत संघ*** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए 20.11.2014 के आदेश में भी दोहराया गया है, जहां याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें आशंका व्यक्त की गई थी कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह आशंका याचिकाकर्ता की पूर्व पत्नी के आवासीय परिसर में की गई तलाशी के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कार्यवाही में कुछ अधिकारियों द्वारा दी गई गिरफ्तारी की कथित धमकियों से उत्पन्न हुई। उन परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका अपरिपक्व थी और कमजोर प्रकथनों पर आधारित थी, यह देखते हुए कि ऐसे प्रकथन प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की आशंका का आधार नहीं बन सकते। इसके बाद उस मामले में रिट याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी करते हुए वापस ले ली गई :

"3. ..... हम आश्वस्त हैं कि याचीगण को इन रिट याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है, जब भी इस तरह के उपाय करने के लिए कोई उचित स्थिति

उत्पन्न होती है, तो उन्हें अपना उपाय करने का अधिकार है।……..”

14. पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत ईडी द्वारा जारी समन के संदर्भ में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने **वीरभद्र सिंह बनाम *प्रवर्तन निदेशालय और अन्य,*** में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

*“143. … संपूर्ण और प्रभावी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों में **"किसी भी व्यक्ति"** को समन भेजने और जांच करने की शक्ति शामिल है। विधि घोषणा करती है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे समन भेजा जाता है, वह सत्य बोलने के लिए बाध्य है। **इस तरह की जांच प्रक्रिया के समय, समन किया गया व्यक्ति अभियुक्त नहीं होता है। मात्र ईसीआईआर का पंजीकरण करना किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं बनाता**। गिरफ्तार होने पर या अभियोजन चलाए जाने पर अंततः वह अभियुक्त बन सकता है। **विधि में कोई भी व्यक्ति पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जारी समन के आदेश से बचने का हकदार नहीं है, इस आधार पर कि भविष्य में उस पर अभियोजन चलाया जाएगा।** पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत बयानों के संबंध में नंदिनी सत्पथी (पूर्वोक्त) में घोषित कानून, और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की समान शक्तियों के संबंध में अन्य घोषणाओं में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनका पूर्ण उत्तर प्रदान करता है।"*

(जोर दिया गया)

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि ईसीआईआर में जांच की अपनी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में ईडी द्वारा समन जारी करने से उन मामलों में याचीगण के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था या उत्पन्न करने का प्रभाव हुआ होगा; और तदनुसार याचिकाओं को तथ्यहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया।

15. तथ्य की दृष्टि से, यह सामान्य आधार है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता जिस बात से व्यथित है वह अनिवार्य रूप से ईडी से प्राप्त समन के आधार पर *गिरफ्तार किए जाने का संभावित खतरा* है; जिस कारण से वह ईसीआईआर को अभिखंडित करने की मांग करता है। याचिकाकर्ता ने ईसीआईआर से उत्पन्न होने वाली ***सभी*** *कार्यवाहियों पर रोक लगाने* और ईडी द्वारा उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रपीड़क कार्रवाई के विरुद्ध अंतरिम राहत की भी मांग की है।

16. यह भी स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को न तो ईसीआईआर में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है; न ही मामले में दायर की गई अभियोजन शिकायत में उसे अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।

17. इस संबंध में, ***हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल*** में उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय का एक संक्षिप्त संदर्भ उपयोगी होगा :

"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक उपबंधों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक शृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में जिसको हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, ***हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है,*** *हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से प्रदर्शित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।*

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में आरोप, एक संज्ञेय अपराध को प्रकट नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 156 (1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है, संहिता की धारा 155(2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश को छोड़कर।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के घटित होने का प्रकटीकरण नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां दंडाधिकारी के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत माना गया है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट विधिक वर्जन है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

(जोर दिया गया)

जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है, उपरोक्त श्रेणियों के मामले केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

18. हालांकि, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी (या, जैसा कि वर्तमान मामले में, ईसीआईआर) को अभिखंडित करना मुख्य रूप से दस्तावेज़ में क्या शामिल है, इस पर आधारित होना चाहिए।

19. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता मुख्य राहत के रूप में ईसीआईआर जैसे दस्तावेज़ को अभिखंडित करना चाहता है जो उसके पास उपलब्ध भी नहीं है। और न ही ईसीआईआर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, ***विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि ईसीआईआर एक आंतरिक दस्तावेज है, इसलिए ईडी के लिए जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति को ईसीआईआर की एक प्रति देना अनिवार्य नहीं है, और ऐसा उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा जिसे केवल पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत समन भेजा गया है।

20. चूंकि न्यायालय के पास ईसीआईआर नहीं है, न ही याचिकाकर्ता विधिक तौर पर ईसीआईआर की एक प्रति दिए जाने का हकदार है, तो ज़ाहिर तौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि न्यायालय उन आधारों का आकलन और

मूल्यांकन कर सके जिन पर याचिकाकर्ता ईसीआईआर अभिखंडित करना चाहता है।

21. दूसरी ओर, हालांकि, ईडी ने इस कार्यवाही में दायर अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता को ईसीआईआर में अभियुक्त के रूप में दर्ज नहीं किया गया है और न ही उसे सीबीआई द्वारा पंजीकृत संज्ञेय अपराध में अभियुक्त के रूप में नामित गया है, जो ईसीआईआर में कार्यवाही का आधार है। प्रस्तुतिकरण के दौरान यह भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले भी 4 अवसरों पर अर्थात 29.01.2021, 15.06.2021, 27.07.2021, 18.08.2023 पर भी समन जारी किया गया था; लेकिन इस तरह के समनों के बाद कभी भी उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया था।

22. यह भी उल्लेखनीय है कि आक्षेपित समन पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जारी किए गए हैं, जिसके उपबंध पर गौर करने की आवश्यकता है। यह निम्नानुसार है :

> ***50. समन करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने, आदि के बारे में प्राधिकारियों की शक्ति***–*(1) निदेशक को, धारा 13 के प्रयोजनों के लिए <u>वही शक्तियां</u> प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय किसी <u>सिविल न्यायालय में निहित होती है</u>, अर्थात्:–*
>
> *(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;*

(ख) किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत किसी रिपोर्टकर्ता इकाई का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करना;

(घ) शपथपत्रों पर साध्य ग्रहण करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

*(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को ऐसे **किसी व्यक्ति** को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के अनुक्रम में माध्य देने के लिए या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है।*

*(3) इस प्रकार समन किए **सभी व्यक्ति**, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, हाजिर होने और ऐसे किसी विषय के बारे में सत्य कथन करने के लिए बाध्य होंगे जिसके संबंध में उनकी परीक्षा की जा रही हो अथवा ऐसे कथन करने और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिनकी उससे अपेक्षा की जाए।*

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई

*अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए **किन्हीं अभिलेखों** को परिबद्ध कर सकेगा और ऐसी किसी अवधि के लिए अपने पास प्रतिधारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे :*

परन्तु कोई सहायक निदेशक या उप निदेशक

(क) किसी अभिलेख को, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना, परिबद्ध नहीं करेगा; या

(ख) ऐसे किसी अभिलेख को निदेशक का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

(जोर दिया गया)

23. स्पष्ट रूप से, पीएमएलए की धारा 50 ईडी के निर्दिष्ट अधिकारियों को एक वाद की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय में निहित शक्तियाँ प्रदान करती है; जिसमें शपथ पर बयान दर्ज करने के लिए किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने की शक्ति शामिल है, इस आदेश के साथ कि इस तरह से समन किया गया कोई भी व्यक्ति उपस्थित होने, उत्तर देने और बयान देने; दस्तावेजों और अभिलेखों की खोज, निरीक्षण और उत्पादन के लिए बाध्य करने; और लिखित में कारण बताकर अभिलेख प्रतिधारित करने और अपने पास रखने के लिए बाध्य होगा।

24. *निश्चित रुप से पीएमएलए की धारा 50 में गिरफ्तारी की शक्ति स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।*

25. यद्यपि पीएमएलए की धारा 19 ईडी के नामित अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, जो उस प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है, यह स्पष्ट है कि गिरफ्तार करने की शक्ति धारा 50 में नहीं है और न ही यह धारा 50 के अंतर्गत जारी समन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है।

26. पूर्णता के लिए, पीएमएलए की धारा 19 को भी यहां उद्धत किया जा सकता है:

> **19.** ***गिरफ्तार करने की शक्ति।***–*(1) यदि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।*
>
> *(2) .....*
>
> *(3) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, चौबीस घंटे के भीतर, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायिक दंडाधिकारी या महानगर दंडाधिकारी के पास ले जाया जाएगा:*
>
> *परंतु चौबीस .....*
>
> (जोर दिया गया)

27. पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों को पेश करने और बयान दर्ज करने की आवश्यकता की शक्ति, जो कि सिविल न्यायालय की शक्तियों के समान है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति से अलग और भिन्न है। ये दो अलग-अलग और विशिष्ट उपबंध हैं। एक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को इस आशंका से रोका नहीं जा सकता कि इससे दूसरे के अधीन शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत दस्तावेज पेश करने या शपथ पर बयान देने के लिए समन किया गया कोई भी व्यक्ति, केवल यह आशंका व्यक्त करते हुए ऐसे समन का विरोध कर सकता है कि उसे ईडी के हाथों, पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति कानूनी योजना के प्रतिकूल होगी।

28. ऊपर संदर्भित उपबंधों और पूर्व निर्णयों के आधार पर; पीएमएलए की धारा 50 के परिशीलन पर जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को समन जारी किया गया है; और यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पीएमएलए के अंतर्गत कार्यवाही में अभियुक्त नहीं है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की इस आशंका से सहमत नहीं है कि उस पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा सकती है।

29. इसके अलावा, इस न्यायालय की राय है कि हालांकि याचिकाकर्ता को एसएफआईओ द्वारा संबंधित कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया था, जो गिरफ्तारी जमानत अपील सं.251/2023 का विषय थी, यह तब भी यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से पीएमएलए के अंतर्गत कार्यवाही में अभियुक्त बनाया ही जाएगा।

30. दूसरी ओर यह अतिव्यापी सिद्धांत है कि न्यायालयों को किसी अपराध की जांच करने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि उच्च न्यायालयों को जांच और विचार में रोक-टोक करने के लिए बिना विचारे अपनी अंतर्निहित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।

31. ऐसा कहा जाने के बाद, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करने के लिए अनिच्छुक होगा कि वर्तमान याचिका दायर करने के अतिरिक्त, उसके पास ईडी के हाथों संभावित विधि-विरुद्ध गिरफ्तारी से स्वयं को बचाने का कोई अन्य तरीका नहीं है और वह विधि से निस्सहाय है। यह न्यायालय स्पष्ट है कि यदि यह वास्तव में सच है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के संबंध में निस्सहाय है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण पूर्ण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाली एक रिट याचिका हमेशा झूठ होगी।

<u>दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत उपचार की उपलब्धता</u>

32. इस संबंध में अपनी अंतश्चेतना को संतुष्ट करने के लिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध उपचार पर कानूनी परिदृश्य और न्यायिक पूर्व निर्णयों की संक्षिप्त रूप से जांच करना आवश्यक समझता है।

33. *विजय मदनलाल चौधरी* (पूर्वोक्त) के निर्णय के सार्थक अध्ययन, जब यह कहता है कि पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांत और कठोरता, अर्थात जमानत प्राप्त करने के लिए उसमें निर्धारित अतिरिक्त जुड़वां शर्तों को पूरा करने की आवश्यकताएं, धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत देने के लिए समान रूप से लागू होंगी, से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को पीएमएलए के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका है तो सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का उपाय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है। किसी भी स्थिति में, धारा 438 दं.प्र.सं. के प्रारंभिक शब्द : "जब *<u>किसी व्यक्ति</u>* को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है..." (जोर दिया गया) यह भी दर्शाते हैं कि उस धारा में निहित उपाय केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, जिसे गैर-जमानती अपराध के संबंध में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।

34. हालांकि, इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्त की गई चिंता यह है कि ***गुजरात राज्य बनाम चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर*** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपना बयान दर्ज करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ("सीजीएसटी अधिनियम") की धारा 69 (एसआईसी, धारा 70) के अंतर्गत समन किया गया व्यक्ति दं.प्र.सं. की धारा 438 लागू नहीं कर सकता क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 (1) के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति लागू होने से पहले कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है; और इसलिए, ऐसा व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा की मांग कर सकता है; इसलिए, यह तर्क देते हुए कि चूंकि पीएमएलए के अंतर्गत भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, याचिकाकर्ता को *चूड़ामणि* (पूर्वोक्त) के समान ही बाधा का सामना करना पड़ेगा और वह केवल रिट कार्यवाही में राहत मांग सकता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सबसे पहले, चूड़ामणि में 2-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा टिप्पणी सीजीएसटी अधिनियम के संदर्भ में की गई है; और इसके अतिरिक्त, 5-न्यायाधीशों की दो अलग-अलग संविधान पीठों ने ***गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य*** और ***सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली)*** में यह अभिनिर्धारित किया

कि *दं.प्र.सं. की धारा 438(4) में उल्लिखित अपराधों,* अर्थात् भा.दं.सं. के अंतर्गत कुछ यौन अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर ऐसा कोई भी अपराध नहीं है, *जिसे धारा 438 के दायरे से बाहर रखा गया हो।* उपरोक्त दो निर्णयों के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं :

गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य

> *"16. उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए आठ सूत्री संहिता के कुछ नियमों पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलेगा कि उन्हें व्यवहार में लागू करना कितना कठिन है। सातवां प्रस्ताव कहता है:*
>
> *"लोक और राज्य के व्यापक हित की मांग है कि कार्यकारी और राजनीतिक शक्ति के उच्च स्तर पर घोर भ्रष्टाचार से जुड़े आर्थिक अपराधों जैसे गंभीर मामलों में, संहिता की धारा 438 के अंतर्गत विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।"*
>
> "17. ***न्यायालय, भले ही उसकी तीसरी आंख हो, अग्रिम जमानत के स्तर पर भ्रष्टाचार की घोरता का आकलन कैसे कर सकता है? और क्या यह कहना सही होगा कि अभियुक्त की स्पष्टता जमानत खारिज करने के लिए पर्याप्त होगी, यदि आवेदक का आचरण सच होने के लिए बहुत ही भद्दे रंगों में रंगा हुआ है?*** *उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए आठवें प्रस्ताव नियम में कहा गया है:*
>
> *"याचिका में दुर्भावना के केवल सामान्य आरोप अपर्याप्त हैं। न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर संतुष्ट*

होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण आरोप पर्याप्त हैं और आरोप गलत और निराधार प्रतीत होते हैं।"

क्या इस नियम का मतलब, और विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर का तर्क, यह है कि अग्रिम जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक यह आरोप न लगाया जाए (और स्वाभाविक रूप से, दर्शाया भी गया है, क्योंकि केवल आरोप लगाना कभी पर्याप्त नहीं होता) कि प्रस्तावित आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं? ***यह समझने वाली बात है कि यदि दुर्भावना दिखाई जाती है तो सामान्य मामलों में अग्रिम जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन यह समझना आसान नहीं है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन क्यों खारिज कर दिया जाना चाहिए जब तक कि आरोप दुर्भावनापूर्ण न दिखाया जाए।*** *यह, वास्तव में, न्यायिक निर्माण द्वारा नियम बनाने में शामिल जोखिम है।* ***इसलिए, विवेक को विवेक के क्षेत्र में ही रहने दिया जाना चाहिए, इसका प्रयोग निष्पक्षता से किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालयों द्वारा सुधार के लिए विवृत होना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति की सुरक्षा इस दोहरी सुरक्षा में निहित है जो इसके दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।***

"18. ***उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए छठे प्रस्ताव के अनुसार, धारा 438 के अंतर्गत विवेक का प्रयोग मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अग्रिम जमानत देने के चरण में अदालत इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा आरोप झूठा या आधारहीन प्रतीत होता है।*** *अब, धारा 438 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को अग्रिम जमानत देने की शक्ति प्रदान करती है यदि आवेदक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे "गैर-जमानती अपराध" करने के आरोप में गिरफ्तार*

किया जा सकता है। ***हमें इस उपबंध में उन शर्तों को पढ़ने के लिए कोई वारंट नहीं दिखता है जिनके अधीन संहिता की धारा 437(1) के अंतर्गत जमानत दी जा सकती है।*** *वह धारा, गैर-जमानती अपराधों के मामलों में जमानत देने की शक्ति प्रदान करते हुए, एक अपवाद के रूप में प्रदान करती है कि गैर-जमानती अपराध करने के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को "इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा" यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है।* ***यदि यह इरादा था कि धारा 437(1) में निहित अपवाद धारा 438(1) के अंतर्गत राहत के अनुदान को नियंत्रित करेगा, तो विधायिका के लिए बाद वाले खंड में एक समान उपबंध पेश करने से आसान कुछ नहीं होता।*** *हम पहले ही इन दोनों धाराओं के बीच बुनियादी अंतर बता चुके हैं।* ***धारा 437 तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति, जिस पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप है, बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय में पेश किया जाता है या लाया जाता है।*** ***धारा 438 गिरफ्तारी से पहले लागू होती है और वास्तव में, इसे लागू की पूर्व शर्तों में से एक यह है कि जो व्यक्ति इसके अंतर्गत राहत के लिए आवेदन करता है, उसे यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि "उसे गिरफ्तार किया जाएगा", जिसका साफ़ मतलब है कि उसे अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है।*** *जमानत देने या अस्वीकार करने के साथ इस विभेद का संबंध यह है कि धारा 437 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, कुछ ठोस आंकड़े हैं जिनके आधार पर यह दर्शाना संभव है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि आवेदक मृत्यु या*

आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध का दोषी है। ***<u>धारा 438 के अंतर्गत आने वाले मामलों में वह चरण अभी भी आना शेष है और, इसके अंतर्गत मामलों की व्यापकता में, यह प्रतिपादित करना समयपूर्व और वास्तव में मुश्किल होगा कि यह ऐसा विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं या नहीं हैं।</u>*** *धारा 437(1) में जिस विश्वास की बात की गई है, उसकी बुनियाद, जिसके कारण न्यायालय आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता, सामान्य रूप से, प्राथमिकी में निहित अभिकथनों की विश्वसनीयता है।* ***<u>धारा 438 के अंतर्गत आने वाले अधिकांश मामलों में, अपेक्षित विश्वास बनाने के लिए उस डाटा की कमी होगी।</u> यदि धारा 437 में उल्लिखित सभी शर्तों को धारा 438 के प्रावधानों में पढ़ा जाए, तो प्रत्यारोपण बिना विच्छेदन के किया जाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि, उच्च न्यायालय के तार्किकता पर, धारा 438(1) को इस खंड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि आवेदक को जमानत पर रिहा "नहीं किया जाएगा" "यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध का दोषी है"।*** *इस प्रक्रिया में किसी ने इस बात की अनवेक्षा की होगी कि धारा 438(1) के अंतर्गक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ऐसा करने के लिए "उचित समझे", धारा 437 (1) उसी व्यापक शब्दों में जमानत देने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। अभिव्यक्ति "यदि वह उचित समझे", जो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की शक्ति के संबंध में धारा 438 (1) में है, धारा 437 (1) में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।* ***हमें उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को प्रदत्त विवेक के दायरे और परिधि के विस्तार करने के उद्देश्य***

से नहीं, किंतु इसे सीमित करने के उद्देश्य से धारा 438 के पुनर्लेखन का कोई वैध कारण दिखाई नहीं देता है। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं कि आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत केवल इस कारण से नहीं दी जा सकती है कि इसके लिए सजा का प्रावधान आजीवन कारावास है। *परिस्थितियाँ मोटे तौर पर ऐसे मामलों में भी जमानत देने को उचित ठहरा सकती हैं, हालाँकि, न्यायालय किसी भी मामले में अग्रिम जमानत का प्रत्याख्यान करने के लिए स्वतंत्र है यदि उसके पास इस तरह के प्रत्याख्यान को उचित ठहराने वाले तथ्य है।*

* * * * *

"21. ***उच्च न्यायालय ने अपनी चौथी प्रतिपादना में कहा है कि धारा 437 में उल्लिखित सीमाओं के अलावा, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक "विशेष मामला" पेश करना होगा। यह, वस्तुतः, धारा 438 द्वारा प्रदत्त हितकारी शक्ति के पुनः प्रेषण को कम कर देता है। अपनी व्यग्रता में, अन्यथा, यह दर्शाने हेतु कि धारा 438 द्वारा प्रदत्त शक्ति "अनियंत्रित या अबाध" नहीं है, उच्च न्यायालय ने उस शक्ति को संयमित कर दिया है जिसका प्रभाव शक्ति को पूरी तरह से अनियंत्रित कर देगा। यह कहना कि आवेदक को अग्रिम जमानत देने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक "विशेष मामला" पेश करनी होगी, वास्तव में कुछ भी नहीं कहना है।*** *आवेदक को निस्संदेह अग्रिम जमानत देने के लिए मामला पेश करना होगा। परंतु कोई इससे आगे बढ़कर यह नहीं कह सकता कि उसे एक "विशेष मामला" पेश करना होगा।* ***हमें यह नहीं दिखाई देता है कि धारा 438 के***

*प्रावधानों पर यह संदेह क्यों किया जाना चाहिए कि इसमें कुछ अस्थिर या उत्तेजक चीज़ शामिल है, जिसे कल्पना की जा सकने वाली सबसे बड़ी सतर्कता और सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। **न्यायिक शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग अनिवार्य रूप से उन बुरे परिणामों का ध्यान रखता है जो इसके असंयमित उपयोग से उत्पन्न होने की संभावना है। प्रत्येक प्रकार के न्यायिक विवेक का, चाहे मामले की प्रकृति कुछ भी हो, जिसके संबंध में इसका प्रयोग अपेक्षित हो, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। वास्तव में, उस संदर्भ के बारे में जागरूकता जिसमें विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है और इसके उपयोग के उचित रूप से अनुमानित परिणामों के बारे में जागरूकता, न्यायिक विवेक के विवेकपूर्ण प्रयोग की पहचान है।** किसी को भी अग्रिम जमानत देने की शक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए।*

* * * * *

*"27. उन निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जो सामान्य जमानत के अधिकार से संबंधित हैं क्योंकि वह अधिकार अग्रिम जमानत के अधिकार के बिल्कुल समानांतर नहीं है। **यद्यपि, यह रोचक बात है कि 1924 में नागेंद्र बनाम राजा-सम्राट [ए.आई.आर. 1924 कैल 476,479,480:25 सी.आर.आई.एल.जे. 732] मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि <u>जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, इस प्रश्न के समाधान में उचित परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या जमानत दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दी जानी चाहिए, क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण</u>***

<u>हेतु उपस्थित होगा और यह निर्विवाद है कि सजा के तौर पर जमानत विधारित नहीं की जानी चाहिए।</u>**.....**

* * * * *

"31. ***अग्रिम जमानत के संबंध में, यदि प्रस्तावित आरोप न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों से नहीं अपितु किसी गुप्त उद्देश्य से उत्पन्न होता प्रतीत होता है, <u>जिसका उद्देश्य आवेदक को गिरफ्तार करके उसे घायल करना और अपमानित करना है</u>, <u>गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश आम तौर पर दिया जाएगा।</u>*** *दूसरी ओर, यदि आवेदक के पूर्ववृत्त को देखते हुए यह संभावना प्रतीत होती है कि वह अग्रिम जमानत के आदेश का लाभ उठाकर न्याय से भाग जाएगा, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। परंतु* ***इन प्रतिपादनाओं का संपरिवर्तन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है।*** *कहने का तात्पर्य यह है कि,* ***<u>इसे एक कठोर नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अग्रिम जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रस्तावित आरोप असद्भावपूर्वक न लगे;</u>*** *और, समान रूप से, यदि आवेदक के फरार होने का कोई डर नहीं है तो अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। कई अन्य विचार भी हैं, जिनका प्रगणन करना बहुत कठिन है, जिनके संयुक्त प्रभाव को न्यायालय को अग्रिम जमानत देते या अस्वीकार करते समय ध्यान देना चाहिए।* ***प्रस्तावित आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, उन घटनाओं का संदर्भ जिनके कारण आरोप लगाए जाने की संभावना है, विचारण में आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित न होने की उचित संभावना, एक उचित आशंका कि साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और " जनता या राज्य के व्यापक हित" कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें न्यायालय को अग्रिम जमानत***

के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखना होता है। .....

* * * * *

"37. तीसरा, ***<u>प्राथमिकी दायर करना धारा 438 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग की पूर्व शर्त नहीं है</u>***। ***<u>एक उचित विश्वास के आधार पर संभावित गिरफ्तारी की संभावना को दर्शाया जा सकता है, भले ही प्राथमिकी अभी तक दायर न की गई हो।</u>***

(जोर दिया गया)

<u>सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली)</u>

"63. ***इसलिए, स्पष्ट रूप से, <u>जहां संसद संहिता की धारा 438 के अंतर्गत न्यायालयों की शक्ति को अपवर्जित करना या प्रतिबंधित करना चाहती थी, उसने स्पष्ट शब्दों में ऐसा किया।</u> नागरिकों के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए संसद की चूक, अग्रिम जमानत मांगने के अधिकार से अन्य अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को, आवश्यक रूप से यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि <u>न तो यह न्यायालय एक व्यापक प्रतिबंध में अनुमान लगा सकता है, और न ही विवेक के प्रयोग में अनम्य दिशानिर्देशों पर जोर दिया जा सकता है - जो न्यायिक विधान के समान होगा।</u>***

* * * * *

"75. ***उपरोक्त कारणों से, इस पीठ को दिए गए संदर्भ में पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि <u>धारा 438(4) में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर, ऐसा कोई अपराध नहीं है, जिसे धारा 438 के दायरे से बाहर रखा गया हो। दूसरे शब्दों में, सभी अपराधों के संबंध में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दी जा सकती है।</u> साथ ही, यदि किसी विशेष***

विधि या क़ानून में यह उपदर्शित है, जो धारा 438(1) के अंतर्गत राहत को अपवर्जित करते हैं, तो उन पर विधिवत विचार करना होगा। *साथ ही, क्या किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में जहां अपराधों के कृत्य से संबंधित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, कुछ विशेष शर्तों के साथ, एक विवेक का मामला है, अपराधों की प्रकृति, दर्शाए गए तथ्यों, आवेदक की पृष्ठभूमि, उसके न्याय से भागने की संभावना (या न्याय से न भागने की संभावना), जांच एजेंसी या पुलिस के साथ सहयोग या असहयोग की संभावना आदि को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। ऐसी कोई अनम्य समय-सीमा नहीं हो सकती जिसके लिए अग्रिम जमानत का आदेश जारी रखा जा सके।*

* * * * *

"न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष

91. न्या. एम.आर. शाह, और न्या. एस रवींद्र भट, के साथ न्या. अरुण मिश्रा, न्या. इंदिरा बनर्जी और न्या. विनीत सरन, के सहमत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ के निम्नलिखित उत्तर दिए गए हैं:

* * * * *

"92. ***यह न्यायालय, दो निर्णयों में उपरोक्त चर्चा के आलोक में, और संदर्भ के उत्तरों के आलोक में, स्पष्ट करता है कि दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत आवेदनों से निपटते समय न्यायालयों को निम्नलिखित को ध्यान में रखना होगा:***

92.1. गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य के [गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565: 1980 एससीसी (सीआरआई) 465] निर्णय के अनुरूप, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की आशंका की

शिकायत करता है और आदेश के लिए संपर्क करता है, आवेदन एक या अन्य विशिष्ट अपराध से संबंधित ठोस तथ्यों (और अस्पष्ट या सामान्य आरोपों पर नहीं) पर आधारित होना चाहिए। अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन में अपराध से संबंधित आवश्यक तथ्य शामिल होने चाहिए, और आवेदक को उचित रूप से गिरफ्तारी की आशंका क्यों है, साथ ही कहानी का उसका पक्ष भी होना चाहिए। ये न्यायालय के लिए आवश्यक हैं जिसे उसके आवेदन पर विचार करना चाहिए, खतरे या आशंका, इसकी गंभीरता या गंभीरता और लगाई जाने वाली किसी भी शर्त की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना चाहिए। ***यह आवश्यक <u>नहीं</u> है कि प्राथमिकी दायर होने के बाद ही कोई आवेदन दायर किया जाना चाहिए; इसे पहले भी पेश किया जा सकता है, जब तक तथ्य स्पष्ट हों और गिरफ्तारी की आशंका के लिए उचित आधार मौजूद हो।"***

(जोर दिया गया)

35. हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि *गुरबख्श सिंह सिबिया* (पूर्वोक्त) और *सुशीला अग्रवाल* (पूर्वोक्त) में जो कहा गया है वह सामान्य प्रतिपादनाएं हैं; लेकिन चूंकि पीएमएलए सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत शासन के समान है क्योंकि यह एक प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार नहीं करता है, बल्कि केवल न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने पर विचार करता है, *चूड़ामणि* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियां

याचिकाकर्ता के आड़े आएंगी। आगे यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत समन किया गया व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में निहित संरक्षण के अंतर्गत अभियुक्त नहीं है, और चूंकि दं.प्र.सं. की धारा 438 लागू करने के लिए "अभियुक्त" होने की आवश्यकता है, इसलिए याचिकाकर्ता, जो अभियुक्त नहीं है, लेकिन केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत समन किया जा रहा है, वह दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार नहीं हो सकता है।

36. उपरोक्त आशंका के उत्तर के लिए दं.प्र.सं. की धारा 438 को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है :

> ***438. गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश–*** *(1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह <u>विश्वास करने का कारण</u> है कि उसे <u>गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है</u>, वह इस धारा के अंतर्गत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा; और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद, अर्थात:–*
>
> *(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;*

(ii) आवेदक के पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या उसे किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर पहले कभी कारावास हुआ है;

(iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; और

(iv) जहां आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है,

या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर देगा या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा।

परंतु, जहां उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उप-धारा के अंतर्गत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है, तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसे आवेदन में लगाए गए आरोप के आधार पर आवेदक को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।

(1-क) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत अंतरिम आदेश देता है, यह तुरंत कम से कम सात दिनों का नोटिस जारी करेगा, साथ ही ऐसे आदेश की एक प्रति लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को तामील कराएगा, ताकि जब न्यायालय द्वारा आवेदन पर अंतिम सुनवाई की जाए तब लोक अभियोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जा सके।

(1-ख) अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति आवेदन की अंतिम सुनवाई और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय अनिवार्य होगी, यदि लोक

अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायालय ऐसी उपस्थिति को न्याय के हित में आवश्यक मानता है।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं -

(i) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;

(ii) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;

(iii) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय

जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला दंडाधिकारी यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376 कख या धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की किसी भी दशा में लागू नहीं होगी।

(जोर दिया गया)

37. इस न्यायालय की राय में, दं.प्र.सं. की धारा 438 में औपचारिक आरोप की आवश्यकता नहीं है और "*गिरफ्तार किया जा सकता है*" और "*आरोप पर*" शब्दों के बाद "*सकता है*" शब्द का अर्थ है कि *गिरफ्तारी* और *आरोप* दोनों *पूर्वानुमानित* हैं। अर्थात्, सबसे पहले, धारा 438 के अंतर्गत एक आवेदन केवल उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दूसरा, धारा 438 के अंतर्गत एक आवेदन इस बात की परवाह किए बिना दायर किया जा सकता है कि कोई औपचारिक आरोप (जैसे प्राथमिकी) है या नहीं, जिसका अर्थ होगा कि पीएमएलए के अंतर्गत एक मामले में अभियोजन शिकायत है या नहीं।

38. हालांकि कोई व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के अंतर्गत केवल बाद में अर्थात् औपचारिक रूप से अभियुक्त बनाए जाने के बाद ही सुरक्षा ले सकता है, दूसरी ओर, एक व्यक्ति दं.प्र.सं. धारा 438 के अंतर्गत पहले अर्थात गिरफ्तारी और अभियोग दोनों से पहले राहत मांग सकता है। पीएमएलए के संदर्भ में धारा 438 के प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या करना गुरबख्श सिंह सिब्बिया (पूर्वोक्त) और सुशीला अग्रवाल (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय की दो संविधान पीठ के निर्णयों के विपरीत होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करना, अर्थात औपचारिक अभियोग, दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन दायर करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है।

39. संपूर्णता के लिए, यह भी देखा जा सकता है कि पीएमएलए की धारा 65 दं.प्र.सं. के उपबंधों को अन्य बातों के साथ-साथ पीएमएलए के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी पर भी लागू करती है "... जहां तक वे पीएमएलए के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हैं ..."। यह सुनिश्चित करने के लिए, हालांकि पीएमएलए की धारा 71 में एक गैर-अस्थिर खंड शामिल है, पीएमएलए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय को उचित मामले में दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत राहत देने से रोकता है। एकमात्र शर्त यह है कि पीएमएलए की धारा 45 में दोहरी शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसलिए इस न्यायालय

की राय में, किसी व्यक्ति के लिए दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत एक आवेदन बनाए रखने के लिए अभियोजन शिकायत दायर करने की विधि में कोई आवश्यकता नहीं है। पीएमएलए की धारा 45 में निहित कठोर दोहरी शर्तों को छोड़कर, पीएमएलए में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो दं.प्र.सं. धारा 438 के उपबंधों को संशोधित करता हो।

40. वास्तव में यह प्रत्यर्थी का मत है कि याचिका धारणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास ईसीआईआर या अभियोजन शिकायत को अभिखंडित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें वह आरोपी नहीं है। प्रत्यर्थी ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता के लिए दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन के माध्यम से एक वैकल्पिक, प्रभावी उपाय उपलब्ध है, जिसे वह *उचित स्तर पर* लेने का हकदार होगा।

41. इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय फिर से दोहराएगी कि पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति अनियंत्रित नहीं है। प्राधिकारियों के पास किसी को अपनी इच्छानुसार गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले तीन प्रकार की आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए:

सबसे पहले, निदेशक को यह उचित विश्वास होना चाहिए कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पीएमएलए के अंतर्गत अपराध का दोषी है, न कि किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत;

दूसरा, ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए; और

तीसरा, ऐसा विश्वास उस सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो निदेशक के पास है।

42. इन तीन शर्तों में जोड़ने के लिए, धारा 19 में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने और "... ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ..." उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ गिरफ्तारी के आदेश की एक प्रति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अग्रेषित करने की भी आवश्यकता होती है। फिर, निश्चित रूप से, एक आवश्यकता यह भी है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक ले जाने के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है। ***वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य*** मामले में अपने हालिया निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 19(1) के आदेश का

अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी ही निष्फल हो जाएगी; और यह भी कि धारा 19(2) का अनुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है जो किसी अपवाद को बर्दाश्त नहीं करता है।

<u>निष्कर्ष</u>

43. उपर्युक्त कारणों से, यह न्यायालय आक्षेपित ईसीआईआर को अभिखंडित करने की मांग करने वाली वर्तमान रिट याचिका पर विचार करना आवश्यक नहीं समझता है, *क्योंकि याचिका अपरिपक्व है।*

44. एक बार जब इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर लिया कि अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन इस बात के बावजूद विचारणीय है कि याचिकाकर्ता का नाम ईसीआईआर या अभियोजन की शिकायत में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं है, तो यह न्यायालय इस बात पर विचार नहीं कर सकता है कि क्या संबंधित न्यायालय जिसके समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया है, याचिकाकर्ता को राहत देगा या नहीं। नतीजतन, स्थापित विधिक स्थिति के मद्देनज़र, जैसा कि ***निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोहराया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार कोई अंतरिम राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

45. यह न्यायालय यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करेगा कि वर्तमान निर्णय का तात्पर्य यह नहीं है कि उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से वर्जित है जो किसी अनुसूचित अपराध में, या ईसीआईआर से उत्पन्न अभियोजन अनुपालन में नामित अभियुक्त नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह विधि की सुस्थापित स्थिति का अवमूल्यन होगा जैसा कि एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के मशहूर निर्णय में बताया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए, संवैधानिक न्यायालयों की पूर्ण शक्तियों पर कोई भी सीमा केवल स्व-लगाया गया है, और कोई *"सीधे व किताबी सिद्धांत" नहीं हो सकते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उसने संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत निहित असाधारण शक्तियों को "निरोध, कैद और सीमित" कर दिया है"।*

46. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

47. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटान किया जाता है।

न्या. अनूप जयराम भंभानी

19 अक्टूबर, 2023
डीएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*